

M.A. 1st Semester

Public Finance

Paper code - A080703T

1. लोक वित्त (Public Finance) क्या है? इसके मुख्य क्षेत्र क्या हैं?

उत्तर:

लोक वित्त (Public Finance) अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सरकार की आय (Income), व्यय (Expenditure), ऋण (Debt) और वित्तीय प्रशासन (Financial Administration) का अध्ययन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के आर्थिक कल्याण (Economic Welfare) को अधिकतम करना और संसाधनों का सही आवंटन करना है। निजी वित्त के विपरीत, जहाँ व्यक्ति अपनी आय के अनुसार व्यय तय करता है, लोक वित्त में सरकार पहले अपने व्यय के लक्ष्यों का निर्धारण करती है और फिर उसी आधार पर आय के स्रोत जुटाती है।

लोक वित्त के मुख्यतः चार प्रमुख क्षेत्र होते हैं:

सार्वजनिक आय (Public Revenue): इसमें कर (Taxes), गैर-कर राजस्व (Non-tax revenues), और शुल्क शामिल हैं।

सार्वजनिक व्यय (Public Expenditure): इसमें विकासत्मक और गैर-विकासत्मक कार्यों पर सरकार द्वारा किया जाने वाला खर्च शामिल होता है।

सार्वजनिक ऋण (Public Debt): जब सरकार का खर्च आय से अधिक हो जाता है, तो वह आंतरिक या बाह्य स्रोतों से ऋण लेती है।

वित्तीय प्रशासन और नीति (Financial Administration & Fiscal Policy): इसमें बजट निर्माण, लेखा-परीक्षा (Audit) और राजकोषीय नीति का संचालन आता है।

प्रो. डाल्टन के अनुसार, "लोक वित्त सार्वजनिक अधिकारियों के आय और व्यय तथा उनके एक-दूसरे के साथ समायोजन की जांच करता है।" यह विषय विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में केंद्रीय भूमिका निभाता है।

2. निजी वित्त (Private Finance) और सार्वजनिक वित्त (Public Finance) में मुख्य अंतर क्या हैं?

उत्तर:

निजी वित्त किसी व्यक्ति या निजी संस्था की वित्तीय गतिविधियों से संबंधित होता है, जबकि सार्वजनिक वित्त पूरी सरकार (केंद्रीय, राज्य व स्थानीय) के वित्तीय संचालन से संबंधित है। दोनों में निम्नलिखित प्रमुख अंतर हैं:

आय और व्यय का निर्धारण: व्यक्ति पहले अपनी आय देखता है और फिर व्यय की योजना बनाता है, जबकि सरकार पहले अपने व्यय का अनुमान लगाती है और फिर आय जुटाने का प्रयास करती है।

उद्देश्य: निजी वित्त का प्राथमिक उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ या उपयोगिता को अधिकतम करना होता है। इसके विपरीत, लोक वित्त का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण और जनहित को बढ़ावा देना है।

ऋण लेने की क्षमता: सरकार आवश्यकता पड़ने पर आंतरिक (जनता व बैंकों) और बाह्य (अंतरराष्ट्रीय संस्थानों) दोनों स्रोतों से ऋण ले सकती है तथा नोट छापकर भी धन जुटा सकती है। व्यक्ति के पास ऐसे असीमित विकल्प नहीं होते।

बजट की प्रकृति: किसी व्यक्ति के लिए बचत का बजट (Surplus Budget) अच्छा माना जाता है, जबकि सरकार के लिए अक्सर घाटे का बजट (Deficit Budget) आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त माना जाता है।

गोपनीयता: निजी वित्त गोपनीय रहता है, जबकि सार्वजनिक वित्त पारदर्शी और संसद व जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला विषय है।

इन अंतर्गत् के बावजूद, दोनों ही का मुख्य लक्ष्य उपलब्ध सीमित संसाधनों का कुशल और इष्टतम उपयोग करना होता है।

3. डाल्टन का अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत (Dalton's Principle of Maximum Social Advantage) क्या है?

उत्तर:

प्रो. ह्यू डाल्टन द्वारा प्रतिपादित 'अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत' लोक वित्त का एक मूलभूत नियम है। इस सिद्धांत के अनुसार, सरकार की राजकोषीय गतिविधियों (कर लगाने और खर्च करने) का संचालन इस प्रकार होना चाहिए कि समाज को अधिकतम कुल शुद्ध लाभ (Maximum Net Social Benefit) प्राप्त हो सके।

यह सिद्धांत दो प्रमुख अवधारणाओं पर आधारित है:

सीमांत सामाजिक त्याग (Marginal Social Sacrifice - MSS): जब सरकार जनता पर कर लगाती है, तो जनता को अपनी क्रय शक्ति का त्याग करना पड़ता है, जिससे उन्हें कष्ट या असंतोष होता है। जैसे-जैसे कर की मात्रा बढ़ती है, सीमांत सामाजिक त्याग भी बढ़ता जाता है।

सीमांत सामाजिक लाभ (Marginal Social Benefit - MSB): जब सरकार करों से प्राप्त धन को सार्वजनिक कार्यों पर खर्च करती है, तो समाज को लाभ प्राप्त होता है। हालांकि, जैसे-जैसे सार्वजनिक व्यय बढ़ता है, उससे मिलने वाला सीमांत सामाजिक लाभ घटने लगता है (घटते सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार)।

संतुलन की स्थिति:

सामाजिक लाभ तब अधिकतम होता है जब सीमांत सामाजिक त्याग (MSS) = सीमांत सामाजिक लाभ (MSB) हो।

यदि $MSB > MSS$ है, तो सरकार को व्यय और कर और बढ़ाने चाहिए।

यदि $MSS > MSB$ है, तो कर का बोझ अधिक है और सरकार को इसे घटाना चाहिए।

जहाँ दोनों रेखाएँ एक-दूसरे को काटती हैं, वही बिंदु अधिकतम सामाजिक लाभ की स्थिति को दर्शाता है।

4. मस्कग्रेव का लोक वित्त का त्रि-कार्यात्मक ढांचा (Musgrave's Three Branches of Public Finance) क्या है?

उत्तर:

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रिचर्ड मस्कग्रेव (Richard Musgrave) ने सरकार की आर्थिक भूमिका और लोक वित्त के कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए एक तीन-स्तरीय ढांचा प्रस्तुत किया। उनके अनुसार राजकोषीय नीति को निम्नलिखित तीन प्रमुख कार्य निपटाने होते हैं:

आवंटन कार्य (Allocation Branch): इसका मुख्य कार्य अर्थव्यवस्था के संसाधनों को निजी और सार्वजनिक वस्तुओं के बीच कुशलतापूर्वक आवंटित करना है। बाजार तंत्र अक्सर सार्वजनिक वस्तुओं (जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सड़कें) का निर्माण करने में विफल रहता है। अतः सरकार करों और सब्सिडी के माध्यम से यह तय करती है कि संसाधनों का सही उपयोग हो।

वितरण कार्य (Distribution Branch): इसका उद्देश्य समाज में धन और आय के वितरण में न्यायसंगतता (Equity) लाना है। बाजार अर्थव्यवस्था में आय की असमानताएँ बढ़ सकती हैं। सरकार प्रगतिशील कर प्रणाली (Progressive Taxation) और कल्याणकारी योजनाओं (जैसे पेंशन, मुफ्त राशन) के माध्यम से धन का पुनर्वितरण करती है।

स्थिरीकरण कार्य (Stabilization Branch): इसका लक्ष्य अर्थव्यवस्था में उच्च रोजगार स्तर, मूल्य स्थिरता (कम मुद्रास्फीति) और सतत आर्थिक वृद्धि दर बनाए रखना है। मंदी के समय सरकार खर्च बढ़ाकर और कर घटाकर माँग बढ़ाती है, जबकि मुद्रास्फीति के समय कर बढ़ाकर माँग को नियंत्रित करती है।

मस्कग्रेव का मानना था कि यद्यपि ये तीनों कार्य अलग-अलग दिखते हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से ये एक-दूसरे पर निर्भर करते हैं और राजकोषीय निर्णय लेते समय तीनों का ध्यान रखना आवश्यक है।

5. सार्वजनिक वस्तुएं (Public Goods) और निजी वस्तुएं (Private Goods) में क्या अंतर है?

उत्तर:

अर्थशास्त्र में वस्तुओं का वर्गीकरण उनके उपभोग की विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। सार्वजनिक वस्तुओं और निजी वस्तुओं में मुख्य अंतर निम्नलिखित दो गुणों के आधार पर होता है:

अपवर्जनशीलता (Excludability): क्या किसी व्यक्ति को भुगतान न करने पर वस्तु का उपभोग करने से रोका जा सकता है?

प्रतिद्वंद्विता (Rivalry): क्या एक व्यक्ति द्वारा उपभोग करने से दूसरे के लिए उसकी उपलब्धता कम हो जाती है?

निजी वस्तुएं (Private Goods): यह अपवर्जनीय (Excludable) और प्रतिद्वंद्वी (Rivalrous) होती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक सेब खाते हैं, तो कोई अन्य व्यक्ति उसे नहीं खा सकता, और यदि आप पैसे नहीं देंगे तो दुकानदार आपको सेब नहीं देगा (जैसे: कपड़े, मोबाइल, कार)।

सार्वजनिक वस्तुएं (Public Goods): यह गैर-अपवर्जनीय (Non-excludable) और गैर-प्रतिद्वंद्वी (Non-rivalrous) होती हैं। उदाहरण के लिए, स्ट्रीट लाइट, राष्ट्रीय सुरक्षा या पार्क। किसी एक नागरिक द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा का आनंद लेने से दूसरे नागरिक के लिए सुरक्षा कम नहीं होती, और न ही किसी को इससे वंचित किया जा सकता है।

सार्वजनिक वस्तुओं के मामले में 'मुफ्तखोरी की समस्या' (Free-rider Problem) उत्पन्न होती है, क्योंकि लोग बिना भुगतान किए भी लाभ उठा सकते हैं। इसी कारण निजी क्षेत्र इनका उत्पादन नहीं करता और सरकार को इनका प्रावधान करना पड़ता है।

6. फ्री-राइडर समस्या (Free-Rider Problem) क्या है और यह बाजार विफलता का कारण कैसे बनती है?

उत्तर:

फ्री-राइडर समस्या (Free-Rider Problem) एक ऐसी स्थिति है जहाँ कोई व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का उपयोग बिना उसका भुगतान किए करता है, क्योंकि उसे उस वस्तु का लाभ लेने से रोकना असंभव होता है। यह समस्या मुख्य रूप से सार्वजनिक वस्तुओं (Public Goods) के संदर्भ में उत्पन्न होती है, जो कि गैर-अपवर्जनीय (Non-excludable) होती हैं।

उदाहरण के लिए, यदि कोई शहर स्ट्रीट लाइट लगाता है या राष्ट्रीय रक्षा प्रणाली मजबूत करता है, तो जिन नागरिकों ने कर (Tax) नहीं दिया है, वे भी इस प्रकाश और सुरक्षा का उतना ही लाभ उठाते हैं जितना कि कर देने वाले लोग। चूंकि कोई भी व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से भुगतान किए बिना लाभ पा सकता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति इसके लिए भुगतान करने के लिए तैयार नहीं होता।

बाजार विफलता का कारण:

निजी कंपनियां लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करती हैं। जब वे देखती हैं कि ग्राहक किसी वस्तु के लिए सीधे भुगतान करने को तैयार नहीं हैं (क्योंकि वे फ्री-राइडर बन सकते हैं), तो निजी क्षेत्र ऐसी वस्तुओं का उत्पादन ही नहीं करता। इसे बाजार विफलता (Market Failure) कहा जाता है।

इस समस्या का समाधान केवल सरकार द्वारा ही किया जा सकता है। सरकार अनिवार्य कर प्रणाली के माध्यम से सभी से धन एकत्र करती है और सार्वजनिक वस्तुओं का प्रावधान करती है, जिससे समाज को ये आवश्यक सुविधाएं मिल पाती हैं।

7. वाह्यताएं (Externalities) क्या हैं? धनात्मक और ऋणात्मक वाह्यताओं को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

वाह्यताएं (Externalities) वे लागतें या लाभ हैं जो किसी आर्थिक गतिविधि (उत्पादन या उपभोग) के कारण किसी तीसरे पक्ष (Third Party) को प्राप्त होते हैं, जो उस गतिविधि में सीधे शामिल नहीं है। वाह्यताओं के लिए बाजार में कोई मूल्य नहीं चुकाया जाता या प्राप्त नहीं किया जाता, जिससे बाजार मूल्य प्रणाली सही संकेत देने में विफल रहती है।

वाह्यताएं दो प्रकार की होती हैं:

ऋणात्मक वाह्यताएं (Negative Externalities): जब किसी कार्य से तीसरे पक्ष को नुकसान या लागत झेलनी पड़ती है।

उदाहरण: एक चमड़ा उद्योग नदी में जहरीला पानी बहाता है या धुआँ छोड़ता है। इससे आसपास के लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और जलीय जीवन नष्ट होता है। कारखाना इस प्रदूषण की लागत नहीं चुकाता, जिससे वस्तु की सामाजिक लागत (Social Cost) निजी लागत (Private Cost) से अधिक हो जाती है।

धनात्मक वाह्यताएं (Positive Externalities): जब किसी कार्य से तीसरे पक्ष को बिना किसी भुगतान के लाभ मिलता है।

उदाहरण: यदि कोई व्यक्ति अपने घर के बाहर पौधे लगाता है या टीकाकरण (Vaccination) करवाता है, तो इससे दूसरों को बीमारी फैलने का खतरा कम होता है। यहाँ सामाजिक लाभ (Social Benefit) निजी लाभ (Private Benefit) से अधिक होता है।

सरकार ऋणात्मक वाह्यताओं पर पीगोवियन टैक्स (Pigouvian Tax) लगाकर उन्हें नियंत्रित करती है और धनात्मक वाह्यताओं को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी (Subsidy) प्रदान करती है।

8. मेरिट वस्तुएं (Merit Goods) और डेमेरिट वस्तुएं (Demerit Goods) क्या हैं?

उत्तर:

रिचर्ड मस्कग्रेव द्वारा प्रस्तुत 'मेरिट वस्तुओं' की अवधारणा ऐसी वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित है, जिन्हें सरकार समाज के लिए अत्यधिक आवश्यक मानती है, भले ही उपभोक्ता स्वयं उनकी सही उपयोगिता को न समझ पाते हों।

मेरिट वस्तुएं (Merit Goods): ये वे वस्तुएं हैं जिनका सामाजिक लाभ व्यक्तिगत लाभ से बहुत अधिक होता है। उपभोक्ता अज्ञानता या दूरदर्शिता की कमी के कारण इनका उपभोग कम मात्रा में करते हैं।

उदाहरण: प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण, और पुस्तकालय।

सरकारी भूमिका: सरकार इन वस्तुओं का प्रावधान स्वयं करती है या इन्हें पूरी तरह मुफ्त/कम दरों (Subsidized) पर उपलब्ध कराती है ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी इनका लाभ उठा सकें।

डेमेरिट वस्तुएं (Demerit Goods): ये वे वस्तुएं हैं जिनका सामाजिक नुकसान व्यक्तिगत नुकसान से कहीं अधिक होता है और इनका उपभोग समाज तथा व्यक्ति दोनों के लिए हानिकारक होता है।

उदाहरण: शराब, सिगरेट, नशीले पदार्थ, और जुआ।

सरकारी भूमिका: सरकार इन वस्तुओं के उपभोग को हतोत्साहित करने के लिए इन पर बहुत भारी कर (Sin Tax) लगाती है, इन पर प्रतिबंध लगाती है या विज्ञापन को सीमित करती है।

मेरिट और डेमेरिट वस्तुओं के मामले में सरकार उपभोक्ता की संप्रभुता (Consumer Sovereignty) में हस्तक्षेप करके सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता देती है।

9. प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) और अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) में क्या अंतर है? दोनों के गुण-दोष बताइए।

उत्तर:

कर सरकार का आय का मुख्य स्रोत हैं। कराघात (Impact of Tax) और करापात (Incidence of Tax) के आधार पर करों को दो भागों में बांटा जाता है:

प्रत्यक्ष कर (Direct Tax): जिस व्यक्ति पर यह कर लगाया जाता है, वही इसका अंतिम भुगतान करता है। इसका भार दूसरों पर नहीं टाला जा सकता (कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर होता है)।

उदाहरण: आयकर (Income Tax), निगम कर (Corporate Tax), संपत्ति कर।

गुण: यह न्यायसंगत (प्रगतिशील) होता है, इससे निश्चित आय मिलती है, और इसमें नागरिक चेतना बढ़ती है।

दोष: इसमें कर चोरी की संभावना अधिक होती है, और यह काम करने तथा बचत करने की प्रेरणा को कम कर सकता है।

अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax): यह कर लगाया किसी एक व्यक्ति (या विक्रेता) पर जाता है, लेकिन वह इसका भार उपभोक्ता पर स्थानांतरित कर देता है (कराघात विक्रेता पर, करापात उपभोक्ता पर)।

उदाहरण: माल एवं सेवा कर (GST), सीमा शुल्क (Customs Duty)।

गुण: इसे छुपाना कठिन होता है (कर चोरी कम), यह व्यापक आधार वाला होता है, और इसे वसूलना आसान होता है।

दोष: यह प्रतिगामी (Regressive) होता है क्योंकि यह अमीर और गरीब दोनों पर समान दर से लगता है, जिससे महंगाई बढ़ सकती है।

एक आदर्श कर प्रणाली में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का संतुलित मिश्रण होना चाहिए।

10. कराघात (Impact), करापात (Incidence) और कर-विवर्तन (Tax Shifting) में क्या संबंध है

?

उत्तर:

कर प्रक्रिया को समझने के लिए कराघात, कर-विवर्तन और करापात की अवधारणाओं को समझना आवश्यक है:

कराघात (Impact of Tax): कर का प्राथमिक या मौद्रिक आघात उस व्यक्ति पर पड़ता है जिस पर कानूनन कर लगाया जाता है। यह वह व्यक्ति है जो सरकारी खजाने में सबसे पहले कर की राशि जमा करता है। उदाहरण के लिए, जब सरकार किसी निर्मित वस्तु पर उत्पाद शुल्क लगाती है, तो इसका पहला आघात निर्माता (Manufacturer) पर पड़ता है।

कर-विवर्तन (Tax Shifting): जब वह व्यक्ति जिस पर कर लगाया गया है, कर के भार को किसी अन्य व्यक्ति पर स्थानांतरित करने में सफल हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को 'कर-विवर्तन' कहते हैं।

यह दो प्रकार का हो सकता है: आगे की ओर विवर्तन (Forward Shifting) - निर्माता द्वारा मूल्य बढ़ाकर उपभोक्ता पर भार डालना; और पीछे की ओर विवर्तन (Backward Shifting) - कच्चा माल बेचने वाले या मजदूरों की मजदूरी घटाकर भार पीछे धकेलना।

करापात (Incidence of Tax): कर का अंतिम मौद्रिक भार उस व्यक्ति पर पड़ता है जो कर को आगे स्थानांतरित करने में असमर्थ होता है। यह वही व्यक्ति है जिसकी जेब से अंततः पैसा जाता है।

संबंध:

कराघात प्रारंभिक बिंदु है, कर-विवर्तन प्रक्रिया है, और करापात अंतिम बिंदु है। प्रत्यक्ष करों में कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर होता है (कोई विवर्तन नहीं होता)। जबकि अप्रत्यक्ष करों में विवर्तन के माध्यम से कराघात विक्रेता पर और करापात अंतिम उपभोक्ता पर पड़ता है।

11. एडम स्मिथ के कर रोपण के चार नियम (Adam Smith's Canons of Taxation) कौन से हैं?

उत्तर:

आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक 'द वेल्थ ऑफ नेशंस' (1776) में एक कुशल और न्यायपूर्ण कर प्रणाली के लिए चार प्रमुख नियमों या कैनन्स की व्याख्या की थी, जो आज भी प्रासंगिक हैं:

समता या समानता का नियम (Canon of Equality): इस नियम के अनुसार, कर प्रणाली न्यायपूर्ण होनी चाहिए। नागरिकों को अपनी-अपनी क्षमताओं के अनुसार सरकार को कर देना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि अमीर लोगों पर अधिक दर से और गरीब लोगों पर कम दर से कर लगना चाहिए ताकि कर का वास्तविक बोझ समान रहे।

निश्चितता का नियम (Canon of Certainty): करदाता को कर की राशि, भुगतान का समय, तरीका और कर की दर पूरी तरह स्पष्ट और निश्चित होनी चाहिए। इसमें कोई अनिश्चितता या कर अधिकारियों की मनमानी नहीं होनी चाहिए, ताकि करदाता अपनी वित्तीय योजना बना सके।

सुविधा का नियम (Canon of Convenience): कर की वसूली उस समय और तरीके से की जानी चाहिए जो करदाता के लिए सबसे सुविधाजनक हो। उदाहरण के लिए, किसानों से कर फसल कटने के समय और वेतनभोगियों से कर वेतन मिलने के समय (TDS) लिया जाना चाहिए।

मितव्ययिता का नियम (Canon of Economy): कर एकत्र करने की लागत न्यूनतम होनी चाहिए। यदि कर संग्रह में ही एकत्र की गई राशि का बड़ा हिस्सा खर्च हो जाएगा, तो कर प्रणाली व्यर्थ साबित होगी।

बाद के अर्थशास्त्रियों (जैसे बास्तेबल और डाल्टन) ने इसमें उत्पादकता, लोचशीलता और विविधता के नियम भी जोड़े।

12. कर संरचना के प्रकार: प्रगतिशील (Progressive), आनुपातिक (Proportional), और प्रतिगामी (Regressive) कर क्या हैं?

उत्तर:

कर की दरों और कर योग्य आय (Tax Base) के बीच संबंध के आधार पर कर प्रणालियों को तीन मुख्य भागों में वर्गीकृत किया जाता है:

प्रगतिशील कर (Progressive Tax):

इसमें जैसे-जैसे करदाता की आय बढ़ती है, कर की दर (Tax Rate) भी बढ़ती जाती है।

प्रभाव: यह अमीरों पर अधिक और गरीबों पर कम बोझ डालता है। भारत का आयकर (Income Tax) इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। यह समाज में आय की असमानता को कम करने में मदद करता है।

आनुपातिक कर (Proportional Tax):

इसमें आय का स्तर चाहे जो भी हो, कर की दर सभी के लिए एक समान रहती है।

उदाहरण: यदि कर की दर 10% तय है, तो 1 लाख कमाने वाला ₹10,000 देगा और 10 लाख कमाने वाला ₹1,00,000 देगा। हालांकि कर की राशि अलग है, लेकिन दर समान रहती है। इसे लागू करना आसान है, लेकिन यह सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के पूर्णतः अनुकूल नहीं है।

प्रतिगामी कर (Regressive Tax):

इसमें आय बढ़ने पर कर की दर घटती जाती है, या इसका वास्तविक भार गरीब वर्ग पर अधिक और अमीर वर्ग पर कम पड़ता है।

उदाहरण: बिक्री कर या GST जैसे अप्रत्यक्ष कर। यदि ₹10 के साबुन पर ₹1 का टैक्स है, तो वह ₹1 एक गरीब व्यक्ति की आय का बड़ा हिस्सा होता है, जबकि अमीर की आय का बहुत छोटा हिस्सा।

सामाजिक न्याय और अर्थशास्त्र की दृष्टि से प्रगतिशील कर प्रणाली को सबसे बेहतर माना जाता है।

13. कर देय क्षमता (Capacity to Pay / Ability to Pay Principle) का सिद्धांत क्या है?

उत्तर:

कराधान का 'कर देय क्षमता का सिद्धांत' यह प्रतिपादित करता है कि सरकार को नागरिकों पर कर का भार उनकी कर भुगतान करने की क्षमता के अनुसार डालना चाहिए। जो व्यक्ति जितना अधिक समर्थ है, उसे उतना ही अधिक कर देना चाहिए। यह सिद्धांत सामाजिक न्याय और समानता पर आधारित है।

कर देय क्षमता को मापने के लिए अर्थशास्त्रियों ने दो दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं:

वस्तुनिष्ठ (Objective) या बाह्य मानदंड:

आय (Income): आय को क्षमता का सबसे सटीक मापदंड माना जाता है। अधिक आय = अधिक क्षमता।

संपत्ति (Property): किसी व्यक्ति के पास मौजूद संपत्ति भी उसकी क्षमता दर्शाती है।

व्यय (Expenditure): व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है, यह भी उसकी क्षमता का सूचक है।

विषयनिष्ठ (Subjective) या आंतरिक मानदंड (त्याग का सिद्धांत):

यह सिद्धांत 'घटते सीमांत उपयोगिता के नियम' पर आधारित है। जैसे-जैसे आय बढ़ती है, धन की सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। इसलिए, अमीर व्यक्ति के लिए ₹ 1,000 का मूल्य गरीब व्यक्ति की तुलना में कम होता है।

समान निरपेक्ष त्याग (Equal Absolute Sacrifice): सभी करदाताओं के लिए उपयोगिता का कुल त्याग समान होना चाहिए।

समान आनुपातिक त्याग (Equal Proportional Sacrifice): सभी करदाताओं द्वारा अपनी कुल उपयोगिता का समान प्रतिशत त्याग जाना चाहिए।

समान सीमांत त्याग (Equal Marginal Sacrifice): इसमें समाज का कुल त्याग न्यूनतम होता है, जो प्रगतिशील कर प्रणाली का समर्थन करता है।

14. लाभ का सिद्धांत (Benefit Principle of Taxation) क्या है और इसकी सीमाएं क्या हैं?

उत्तर:

कराधान का लाभ सिद्धांत (Benefit Principle) एरिक लैंडाहल और विकसेल जैसे अर्थशास्त्रियों द्वारा विकसित किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार, किसी नागरिक को सरकार को उतना ही कर देना चाहिए जितना लाभ वह सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सार्वजनिक सेवाओं से प्राप्त करता है। इसे कर का 'व्यापारिक या विनिमय दृष्टिकोण' भी कहा जाता है।

सिद्धार्थ की मुख्य विशेषताएं:

यह कर को एक प्रकार की 'कीमत' (Price) मानता है जो नागरिक सार्वजनिक सेवाओं के बदले सरकार को चुकाते हैं।

जो व्यक्ति सरकारी सेवाओं (जैसे सड़कों, पार्कों) का अधिक उपयोग करता है, उसे अधिक कर देना चाहिए।

सीमाएं और आलोचनाएं:

सार्वजनिक वस्तुओं की प्रकृति: अधिकांश सार्वजनिक वस्तुएं (जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून-व्यवस्था) गैर-अपवर्जनीय होती हैं। यह मापना असंभव है कि किसी विशिष्ट व्यक्ति को सुरक्षा से कितना लाभ मिल रहा है।

कल्याणकारी राज्य के विपरीत: यदि यह नियम लागू किया जाए, तो गरीबों को सरकार से सबसे अधिक सहायता (मुफ्त इलाज, राशन, शिक्षा) मिलती है, अतः उनसे सबसे अधिक कर मांगा जाएगा, जो वे देने में असमर्थ हैं।

फ्री-राइडर समस्या: लोग सरकारी सेवाओं से मिलने वाले अपने वास्तविक लाभ को छुपाएंगे ताकि उन्हें कर न देना पड़े।

इसलिए, आधुनिक लोक वित्त में लाभ के सिद्धांत को केवल कुछ विशिष्ट शुल्कों (Tolls/User fees) तक सीमित माना जाता है, सामान्य कराधान में नहीं।

15. कराधान का मृतभार क्षति (Deadweight Loss of Taxation) या आधिक्य भार (Excess Burden) क्या है?

उत्तर:

जब सरकार किसी वस्तु या आय पर कर लगाती है, तो इससे उपभोक्ताओं और उत्पादकों के व्यवहार में परिवर्तन आता है। कर लगाने के कारण समाज को होने वाली आर्थिक कल्याण की उस शुद्ध हानि को, जो सरकार द्वारा एकत्र

किए गए कर राजस्व से अधिक होती है, मृतभार क्षति (Deadweight Loss) या आधिक्य भार (Excess Burden) कहा जाता है।

यह कैसे उत्पन्न होता है?

मूल्य में विकृति: कर लगने से वस्तु का बाजार मूल्य बढ़ जाता है। उपभोक्ता उस वस्तु की खरीदारी कम कर देते हैं या किसी कम पसंदीदा विकल्प की ओर चले जाते हैं।

उत्पादक और उपभोक्ता अधिशेष में कमी: कर के कारण उपभोक्ता अधिशेष (Consumer Surplus) और उत्पादक अधिशेष (Producer Surplus) दोनों में भारी गिरावट आती है।

राजस्व से अधिक नुकसान: मान लीजिए कर लगने से उपभोक्ता और उत्पादक का कुल कल्याण ₹150 से घट जाता है, लेकिन सरकार को कर के रूप में केवल ₹100 ही प्राप्त होते हैं। यहाँ जो ₹50 का नुकसान हुआ है, वह किसी को प्राप्त नहीं होता; यही 'डेडवेट लॉस' है।

प्रभावित करने वाले कारक:

डेडवेट लॉस की मात्रा माँग और पूर्ति की लोच (Elasticity of Demand and Supply) पर निर्भर करती है। यदि माँग या पूर्ति अधिक लोचदार (Elastic) होगी, तो कर लगाने पर डेडवेट लॉस उतना ही बड़ा होगा। इसलिए, अलोचदार (Inelastic) वस्तुओं पर कर लगाने से डेडवेट लॉस कम होता है।

16. लैफर वक्र (Laffer Curve) क्या दर्शाता है? इसकी नीतिगत प्रासंगिकता क्या है?

उत्तर:

लैफर वक्र (Laffer Curve) की अवधारणा अमेरिकी अर्थशास्त्री आर्थर लैफर (Arthur Laffer) द्वारा 1970 के दशक में प्रस्तुत की गई थी। यह वक्र कर की दर (Tax Rate) और उससे प्राप्त होने वाले कुल कर राजस्व (Total Tax Revenue) के बीच के संबंध को दर्शाता है।

वक्र का आकार और सिद्धांत:

लैफर वक्र एक उल्टे 'U' आकार (Inverted-U shape) का होता है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

शून्य कर दर (0%): यदि कर की दर 0% होगी, तो सरकार को कोई राजस्व नहीं मिलेगा।

100% कर दर: यदि कर की दर 100% कर दी जाए, तो भी सरकार को शून्य राजस्व मिलेगा, क्योंकि लोग काम करने या आय कमाने की प्रेरणा पूरी तरह खो देंगे।

इष्टतम बिंदु (Optimal Tax Rate - T): 0% और 100% के बीच एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ कर की दर पर सरकार को अधिकतम राजस्व प्राप्त होता है।

नीतिगत प्रासंगिकता:

यदि कर की दर इस इष्टतम बिंदु से अधिक बढ़ जाती है, तो उच्च कर दरों के कारण कर चोरी (Tax Evasion), काम न करने की प्रवृत्ति और काले धन को बढ़ावा मिलता है।

ऐसी स्थिति में, यदि सरकार कर की दरों में कटौती करती है, तो आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, कर आधार (Tax Base) बढ़ेगा और कुल कर राजस्व घटने के बजाय बढ़ जाएगा।

इस सिद्धांत का उपयोग 1980 के दशक में अमेरिका में 'रीगनोमिक्स' (Reaganomics) के तहत करों में भारी कटौती करने के लिए तर्क के रूप में किया गया था।

17. कराधान में समता: क्षैतिज समता (Horizontal Equity) और लंबवत समता (Vertical Equity) क्या हैं?

उत्तर:

लोक वित्त में कराधान का एक प्राथमिक लक्ष्य समाज में न्याय और समता (Equity) स्थापित करना है। कर प्रणाली में समता को दो दृष्टिकोणों से देखा जाता है:

क्षैतिज समता (Horizontal Equity):

अवधारणा: "समान स्थिति वाले लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए" (Equals should be treated equally)।

व्याख्या: यदि दो व्यक्तियों की कर देने की क्षमता, आय, और पारिवारिक परिस्थितियाँ समान हैं, तो उन पर कर का भार भी बिल्कुल समान होना चाहिए।

उदाहरण: यदि व्यक्ति A और व्यक्ति B दोनों की वार्षिक आय ₹10 लाख है और दोनों की जिम्मेदारियाँ समान हैं, तो दोनों को एक समान राशि का आयकर देना चाहिए। यदि किसी एक को विशेष छूट दी जाती है, तो यह क्षैतिज समता का उल्लंघन होगा।

लंबवत समता (Vertical Equity):

अवधारणा: "असमान स्थिति वाले लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाना चाहिए" (Unequals should be treated unequally)।

व्याख्या: जिन व्यक्तियों की आय और कर देने की क्षमता अलग-अलग है, उनसे अलग-अलग मात्रा में कर लिया जाना चाहिए। अधिक सामर्थ्य वाले व्यक्ति को कम सामर्थ्य वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक कर देना चाहिए।

उदाहरण: ₹50 लाख कमाने वाले व्यक्ति पर ₹5 लाख कमाने वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक दर (Percentage) से कर लगाना। यही प्रगतिशील कराधान का आधार है।

इन दोनों अवधारणाओं का सही संतुलन ही एक तर्कसंगत और न्यायपूर्ण कर प्रणाली का निर्माण करता है।

18. सार्वजनिक व्यय के वर्गीकरण: विकासत्मक बनाम गैर-विकासत्मक, और योजनागत बनाम गैर-योजनागत व्यय को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

सरकार द्वारा किए जाने वाले सार्वजनिक व्यय के आर्थिक प्रभावों को समझने के लिए इसे विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

विकासत्मक (Developmental) बनाम गैर-विकासत्मक (Non-Developmental) व्यय:

विकासत्मक व्यय: यह वह खर्च है जो देश में उत्पादन क्षमता बढ़ाने, बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और मानव पूंजी का विकास करने में सीधे मदद करता है। उदाहरण: सड़कों, पुलों, बिजली परियोजनाओं का निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर खर्च।

गैर-विकासत्मक व्यय: यह वह खर्च है जो आवश्यक तो है लेकिन इससे प्रत्यक्ष रूप से किसी उत्पादन या परिसंपत्ति (Asset) का निर्माण नहीं होता। उदाहरण: रक्षा खर्च, प्रशासनिक सेवाएं, पुलिस, पेंशन, और पुराने ऋणों पर ब्याज का भुगतान।

योजनागत (Plan) बनाम गैर-योजनागत (Non-Plan) व्यय (भारत में 2017 से पूर्व का वर्गीकरण):

योजनागत व्यय: यह व्यय पंचवर्षीय योजनाओं के तहत तय किए गए विशिष्ट कार्यक्रमों और परियोजनाओं पर किया जाता था।

गैर-योजनागत व्यय: यह सरकार के नियमित कामकाज को चलाने के लिए अनिवार्य खर्च था (जैसे ब्याज भुगतान, सब्सिडी, रक्षा)।

नोट: भारत में 2017-18 के बजट से योजनागत और गैर-योजनागत के भेद को समाप्त कर राजस्व व्यय (Revenue Expenditure) और पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) के रूप में नया और अधिक वैज्ञानिक वर्गीकरण अपना लिया गया है।

19. वैगनर का सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का नियम (Wagner's Law of Increasing State Activities) क्या है?

उत्तर:

जर्मन अर्थशास्त्री एडोल्फ वैगनर (Adolph Wagner) ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औद्योगिक देशों के आंकड़ों का अध्ययन करके 'सार्वजनिक व्यय के निरंतर विस्तार का नियम' प्रतिपादित किया। इसे 'वैगनर का नियम' कहा जाता है।

मुख्य सिद्धांत:

वैगनर के अनुसार, जैसे-जैसे किसी देश में आर्थिक विकास होता है और प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, वैसे-वैसे अर्थव्यवस्था में सरकारी गतिविधियों और सार्वजनिक व्यय का अनुपात राष्ट्रीय आय की तुलना में तेजी से बढ़ता है। अर्थशास्त्रीय भाषा में, सार्वजनिक व्यय की आय लोच (Income Elasticity of Public Expenditure) इकाई से अधिक होती है ($E_y > 1$)।

सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण:

प्रशासनिक और सुरक्षात्मक कार्य: समाज के जटिल होने पर कानून-व्यवस्था, न्याय प्रणाली, और अनुबंधों को लागू करने के लिए अधिक खर्च की आवश्यकता होती है।

कल्याणकारी कार्य: आय बढ़ने पर जनता शिक्षा, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक गतिविधियों और सामाजिक सुरक्षा की अधिक मांग करती है, जिन्हें सरकार को पूरा करना पड़ता है।

बड़े पैमाने के बुनियादी ढांचे: आधुनिक औद्योगिक विकास के लिए ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स (रेलवे, बिजली, संचार) की आवश्यकता होती है जिनमें निजी क्षेत्र जोखिम नहीं लेना चाहता, अतः सरकार को व्यय करना पड़ता है।

बाजार विफलताएं: एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए राज्य का हस्तक्षेप बढ़ता है।

20. वाइसमैन-पिकॉक परिकल्पना (Wiseman-Peacock Hypothesis) क्या है? इसके तीन प्रभाव बताइए।

उत्तर:

ब्रिटिश अर्थशास्त्री जैक वाइसमैन और एलन पिकॉक ने 1890 से 1955 के दौरान ब्रिटेन के सार्वजनिक व्यय के आंकड़ों का अध्ययन करके सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की व्याख्या की। उन्होंने वैगनर के इस विचार को खारिज किया कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि एक निरंतर और चिकनी (Continuous & Smooth) प्रक्रिया है। उनके अनुसार सार्वजनिक व्यय में वृद्धि सीढ़ीदार (Step-like) रूप में होती है।

उन्होंने इसके लिए तीन मुख्य प्रभावों (Effects) की व्याख्या की:

विस्थापन प्रभाव (Displacement Effect): सामान्य समय में जनता करों के एक निश्चित स्तर की आदी होती है। लेकिन युद्ध, अकाल या संकट के समय सरकार को व्यय अचानक बढ़ाना पड़ता है, जिसके लिए वह कर की दरें बढ़ाती है। संकट समाप्त होने के बाद व्यय और कर पुराने स्तर पर वापस नहीं आते, बल्कि एक नए उच्च स्तर पर विस्थापित (Displace) हो जाते हैं।

निरीक्षण प्रभाव (Inspection Effect): संकट के दौरान सरकार और जनता सामाजिक समस्याओं का नए सिरे से निरीक्षण करती हैं। जनता यह महसूस करती है कि सरकार को स्वास्थ्य, शिक्षा और पुनर्वास पर अधिक खर्च करना चाहिए, जिससे नए सार्वजनिक व्यय स्वीकृत हो जाते हैं।

केन्द्रीकरण प्रभाव (Concentration Effect): संकट के समय केंद्रीय सरकार की शक्तियां और व्यय करने की क्षमता प्रांतीय या स्थानीय सरकारों की तुलना में बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिससे कुल लोक वित्त में केंद्र का प्रभुत्व बढ़ जाता है।

21. सार्वजनिक व्यय के प्रभाव: उत्पादन, वितरण और आर्थिक स्थिरता पर क्या प्रभाव पड़ता है?

उत्तर:

आधुनिक अर्थशास्त्र में सार्वजनिक व्यय केवल आय जुटाने और खर्च करने का साधन नहीं है, बल्कि यह अर्थव्यवस्था को दिशा देने वाला एक शक्तिशाली उपकरण है। प्रो. डाल्टन के अनुसार, सार्वजनिक व्यय के प्रभावों को तीन मुख्य क्षेत्रों में देखा जा सकता है:

उत्पादन पर प्रभाव (Effect on Production):

काम करने और बचत करने की क्षमता: जब सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास पर खर्च करती है, तो श्रमिकों की कार्यकुशलता और उत्पादन क्षमता बढ़ती है।

काम करने और बचत करने की इच्छा: यदि सामाजिक सुरक्षा (जैसे बेरोजगारी भत्ता) बहुत अधिक और बिना शर्त दी जाए, तो लोगों में काम करने की इच्छा कम हो सकती है। लेकिन बुनियादी ढांचे पर व्यय से निवेश और बचत को प्रोत्साहन मिलता है।

संसाधनों का आवंटन: सब्सिडी और सार्वजनिक निवेश के माध्यम से संसाधनों को अनुत्पादक क्षेत्रों से हटाकर उत्पादक क्षेत्रों की ओर मोड़ा जा सकता है।

आय के वितरण पर प्रभाव (Effect on Distribution):

यदि सार्वजनिक व्यय गरीबों के कल्याण (मुफ्त शिक्षा, राशन, पेंशन) पर अधिक किया जाता है, तो इससे समाज में धन की असमानता घटती है (प्रगतिशील व्यय)।

आर्थिक स्थिरता पर प्रभाव (Effect on Economic Stability):

मंदी के समय सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करके प्रभावी माँग (Effective Demand) बढ़ाई जाती है, जिससे रोजगार और उत्पादन बढ़ता है (केन्स का दृष्टिकोण)।

अति-मुद्रास्फीति के समय गैर-जरूरी सरकारी व्यय में कटौती करके माँग को नियंत्रित किया जाता है।

22. सार्वजनिक ऋण (Public Debt) क्या है? आंतरिक (Internal) और बाह्य (External) ऋण में क्या अंतर है?

उत्तर:

जब सरकार के नियमित राजस्व (कर व गैर-कर आय) उसके कुल सार्वजनिक व्यय को पूरा करने के लिए अपर्याप्त होते हैं, तो सरकार इस घाटे को पूरा करने के लिए जनता, वित्तीय संस्थाओं या विदेशी संस्थाओं से उधार लेती है। इस एकत्र उधार राशि को सार्वजनिक ऋण (Public Debt) कहा जाता है।

स्रोत के आधार पर सार्वजनिक ऋण को दो भागों में विभाजित किया जाता है:

आंतरिक ऋण (Internal Debt):

परिभाषा: यह ऋण सरकार द्वारा देश की घरेलू सीमाओं के भीतर स्थित नागरिकों, व्यावसायिक बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और अन्य वित्तीय संस्थानों से लिया जाता है।

विशेषता: यह देश की मुद्रा (जैसे भारतीय रुपये) में होता है।

प्रभाव: आंतरिक ऋण देश की कुल राष्ट्रीय आय या संसाधनों में तत्काल कोई बदलाव नहीं लाता; यह केवल समाज के एक वर्ग (ऋणदाताओं) से धन को सरकार के पास स्थानांतरित करता है।

बाह्य ऋण (External Debt):

परिभाषा: यह ऋण विदेशी सरकारों, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं (जैसे विश्व बैंक, IMF, ADB) या विदेशी नागरिकों से लिया जाता है।

विशेषता: यह विदेशी मुद्रा (जैसे अमेरिकी डॉलर) में लिया और चुकाया जाता है।

प्रभाव: बाह्य ऋण लेते समय देश में अतिरिक्त वास्तविक संसाधन आते हैं, लेकिन ब्याज और मूलधन का भुगतान करते समय देश के संसाधन बाहर चले जाते हैं (Real Resource Drain)।

23. उत्पादक ऋण (Productive Debt) और अनुत्पादक ऋण (Unproductive Debt) में क्या अंतर है?

उत्तर:

सार्वजनिक ऋण का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, इसके आधार पर प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों ने ऋणों को उत्पादक और अनुत्पादक ऋणों में वर्गीकृत किया है:

उत्पादक ऋण (Productive or Reproductive Debt):

अर्थ: जब सरकार द्वारा लिया गया ऋण ऐसी परियोजनाओं में निवेश किया जाता है जो सीधे आय उत्पन्न करती हैं या देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाती हैं।

उदाहरण: रेलवे का निर्माण, सिंचाई परियोजनाएं, बिजली संयंत्र, और बुनियादी ढांचे का विकास।

विशेषता: इन परियोजनाओं से भविष्य में निरंतर आय (Income Stream) प्राप्त होती है, जिससे न केवल ऋण का ब्याज चुकाया जा सकता है, बल्कि मूलधन भी वापस किया जा सकता है। ऐसे ऋण अर्थव्यवस्था पर कोई नकारात्मक भार (Burden) नहीं डालते, बल्कि आर्थिक समृद्धि लाते हैं।

अनुत्पादक ऋण (Unproductive or Deadweight Debt):

अर्थ: जब सरकार द्वारा लिया गया ऋण ऐसे कार्यों पर खर्च किया जाता है जिनसे कोई प्रत्यक्ष आय या संपत्ति (Asset) निर्मित नहीं होती।

उदाहरण: युद्ध लड़ने, रक्षा सामग्री खरीदने, अकाल राहत पर खर्च, या प्रशासनिक व्यय और उपभोग के लिए लिया गया ऋण।

विशेषता: इन ऋणों से भविष्य में कोई मौद्रिक आय नहीं होती। इनका ब्याज और मूलधन चुकाने के लिए सरकार को भविष्य में जनता पर अतिरिक्त कर लगाने पड़ते हैं, जिससे समाज पर वास्तविक भार पड़ता है।

24. सार्वजनिक ऋण को चुकाने की विभिन्न विधियां (Methods of Debt Redemption) कौन सी हैं?

उत्तर:

सरकार द्वारा लिए गए सार्वजनिक ऋणों का समय पर भुगतान करना उसकी वित्तीय साख और अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ऋण शोधन (Debt Redemption) की मुख्य विधियां निम्नलिखित हैं:

शोधन निधि (Sinking Fund): सरकार हर साल अपने बजट से एक निश्चित राशि एक विशेष कोष (फंड) में जमा करती है। यह धन ब्याज सह जमा होता रहता है और ऋण की परिपक्वता (Maturity) तिथि पर इससे पूरा कर्ज चुका दिया जाता है। यह सबसे वैज्ञानिक विधि है।

ऋणों का परिवर्तन (Conversion of Debt): जब बाजार में ब्याज दरें गिर जाती हैं, तो सरकार पुराने उच्च-ब्याज वाले ऋणों को नए कम-ब्याज वाले ऋणों में परिवर्तित कर देती है, जिससे ब्याज का भार कम हो जाता है।

पूंजीगत कर (Capital Levy): आपात स्थिति या भारी युद्ध ऋण को चुकाने के लिए सरकार अमीरों की पूंजी या संपत्ति पर एक बार भारी कर (Capital Levy) लगाती है और प्राप्त राशि से कर्ज बेबाक करती है।

वार्षिकी जमा (Terminable Annuities): इसमें सरकार ऋणदाता को प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि देती है, जिसमें ब्याज और मूलधन का एक हिस्सा शामिल होता है। निश्चित वर्षों के बाद ऋण अपने आप समाप्त हो जाता है।

बजट अधिशेष (Budget Surplus): जब सरकार अपने बजट में आय को व्यय से अधिक रखती है, तो बचे हुए अधिशेष से ऋण चुकता किया जाता है।

नया ऋण लेकर पुराना ऋण चुकाना (Refunding): पुराने परिपक्व ऋण को चुकाने के लिए नया ऋण जारी करना।

25. रिकार्डियन तुल्यता (Ricardian Equivalence Theorem) क्या है?

उत्तर:

'रिकार्डियन तुल्यता' (Ricardian Equivalence) लोक वित्त की एक प्रसिद्ध अवधारणा है, जिसे सर्वप्रथम डेविड रिकार्डो ने प्रस्तुत किया था और बाद में 1974 में रॉबर्ट बैरो (Robert Barro) द्वारा इसे आधुनिक राजकोषीय अर्थशास्त्र में पुनर्जीवित किया गया।

मुख्य सिद्धांत:

यह सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि सरकार अपने खर्च का वित्तपोषण कर (Taxes) लगाकर करे या ऋण (Borrowing/Debt) लेकर, इसका अर्थव्यवस्था में कुल मांग (Aggregate Demand) और राष्ट्रीय बचत पर एक समान प्रभाव पड़ता है। अर्थात् दोनों तरीके आर्थिक दृष्टि से एक-दूसरे के तुल्य हैं।

तर्क और प्रक्रिया:

यदि सरकार आज कर बढ़ाने के बजाय ऋण लेकर अपना व्यय पूरा करती है, तो जनता को तात्कालिक रूप से कर राहत मिलती है और उनकी वर्तमान आय बढ़ती है।

हालांकि, तर्कसंगत और दूरदर्शी नागरिक (Rational Consumers) यह समझते हैं कि सरकार को आज लिए गए ऋण और उसके ब्याज को चुकाने के लिए भविष्य में कर बढ़ाने ही पड़ेंगे।

इसलिए, लोग अपनी बढ़ी हुई वर्तमान आय को खर्च (Consumption) करने के बजाय बचत (Save) कर लेते हैं ताकि वे भविष्य में लगने वाले करों का भुगतान कर सकें।

परिणामस्वरूप, निजी उपभोग में कोई वृद्धि नहीं होती और राजकोषीय प्रोत्साहन (Fiscal Stimulus) का कुल माँग पर प्रभाव शून्य हो जाता है।

सीमाएँ: यह सिद्धांत यह मानकर चलता है कि लोग पूरी तरह दूरदर्शी हैं और पूंजी बाजार पूर्ण है, जो वास्तविक दुनिया में हमेशा सत्य नहीं होता।

26. राजकोषीय नीति (Fiscal Policy) क्या है? इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं?

उत्तर:

राजकोषीय नीति (Fiscal Policy) सरकार की वह नीति है जिसके अंतर्गत वह अपने आय (कराधान), व्यय (सार्वजनिक खर्च) और ऋण (सार्वजनिक उधार) के साधनों का प्रयोग देश के आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए करती है। इसका संचालन देश के वित्त मंत्रालय द्वारा बजट के माध्यम से किया जाता है।

राजकोषीय नीति के मुख्य उद्देश्य:

पूर्ण रोजगार प्राप्त करना: मंदी के समय सरकारी व्यय बढ़ाकर नए रोजगार के अवसर पैदा करना।

मूल्य स्थिरता (Price Stability): अति-मुद्रास्फीति (Inflation) को नियंत्रित करने के लिए कर बढ़ाना और सरकारी खर्च घटाना; तथा मंदी (Deflation) को रोकने के लिए कर घटाना।

आर्थिक वृद्धि (Economic Growth): बुनियादी ढांचे, उद्योग और कृषि में सार्वजनिक निवेश बढ़ाकर जीडीपी वृद्धि दर को तेज करना।

आय और धन की असमानता को कम करना: प्रगतिशील कर प्रणाली और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों को सहायता पहुँचाना और धन का पुनर्वितरण करना।

संसाधनों का कुशल आवंटन: सामाजिक रूप से आवश्यक वस्तुओं (जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा) के उत्पादन को प्रोत्साहन देना और हानिकारक वस्तुओं (जैसे तंबाकू) पर भारी कर लगाकर हतोत्साहित करना।

यह मौद्रिक नीति (Monetary Policy - जो केंद्रीय बैंक द्वारा संचालित होती है) के साथ मिलकर अर्थव्यवस्था को संतुलित रखती है।

27. स्वचालित स्थिरीकारक (Automatic Stabilizers) क्या हैं? ये कैसे काम करते हैं?

उत्तर:

स्वचालित स्थिरीकारक (Automatic Stabilizers) राजकोषीय नीति के वे तंत्र या उपकरण हैं जो बिना किसी नए कानून या सरकारी नीतिगत निर्णय के, अर्थव्यवस्था में आने वाले उतार-चढ़ाव (मंदी या मुद्रास्फीति) को स्वतः ही कम करने का प्रयास करते हैं। ये बजट संरचना में ही अंतर्निहित होते हैं।

प्रमुख स्वचालित स्थिरीकारक:

प्रगतिशील आयकर (Progressive Income Tax):

तेजी/मुद्रास्फीति के समय: जब अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है, तो लोगों की आय बढ़ती है। प्रगतिशील कर प्रणाली के कारण लोग स्वचालित रूप से उच्च कर कोष्ठकों (Tax Brackets) में आ जाते हैं और अधिक कर देते हैं। इससे उनकी खर्च योग्य आय घटती है और मुद्रास्फीति पर रोक लगती है।

मंदी के समय: जब लोगों की आय घटती है, तो वे कम कर दरों के दायरे में आ जाते हैं, जिससे करों में स्वतः कमी आती है और लोगों के पास खर्च करने योग्य पैसा बचता है।

सामाजिक सुरक्षा भुगतान और बेरोजगारी भत्ता (Unemployment Benefits):

मंदी के समय: जब बेरोजगारी बढ़ती है, तो सरकार द्वारा दिए जाने वाले बेरोजगारी भत्ते और कल्याणकारी भुगतानों पर खर्च स्वचालित रूप से बढ़ जाता है। इससे अर्थव्यवस्था में मांग बनी रहती है।

तेजी के समय: रोजगार बढ़ने पर भत्तों पर खर्च स्वतः कम हो जाता है।

इनका मुख्य लाभ यह है कि इनके क्रियान्वयन में कोई 'समय पश्चता' (Time Lag) नहीं होती।

28. स्वेच्छिक राजकोषीय नीति (Discretionary Fiscal Policy) क्या है? इसके सीमाएँ बताइए।

उत्तर:

स्वेच्छिक राजकोषीय नीति (Discretionary Fiscal Policy) से तात्पर्य सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में स्थिरता या वृद्धि लाने के लिए जानबूझकर किए गए नीतिगत बदलावों से है। इसमें सरकार कानून बनाकर करों की दरों में बदलाव करती है, नए कर लगाती है, या अपनी व्यय योजनाओं को नए सिरे से बढ़ाती या घटाती है (जैसे राहत पैकेज देना)।

यह दो प्रकार की होती है: विस्तारवादी (Expansionary) - मंदी से निपटने के लिए व्यय बढ़ाना व कर घटाना; और संकुचनकारी (Contractionary) - मुद्रास्फीति रोकने के लिए व्यय घटाना व कर बढ़ाना।

इसकी सीमाएँ और कठिनाइयाँ:

समय पश्चता (Time Lags):

पहचान में देरी (Recognition Lag): मंदी या मुद्रास्फीति का पता चलने में समय लगता है।

निर्णय में देरी (Administrative Lag): संसद से विधेयक पारित कराने में लंबा समय लगता है।

कार्यान्वयन में देरी (Operational Lag): नीति बनने के बाद पैसा वास्तव में खर्च होने और असर दिखने में महीनों लग जाते हैं।

भीड़ प्रभाव (Crowding-out Effect): सरकार द्वारा अधिक ऋण लेने से ब्याज दरें बढ़ जाती हैं, जिससे निजी निवेश घट जाता है।

राजनीतिक दबाव: चुनाव जीतने के लिए सरकारें अक्सर कर बढ़ाने या व्यय घटाने से कतराती हैं, भले ही अर्थव्यवस्था के लिए यह आवश्यक हो।

29. बजट (Budget) क्या है? बजट के मुख्य घटक (Components of Budget) कौन-कौन से हैं?

उत्तर:

बजट एक आगामी वित्तीय वर्ष (भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च) के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों (Revenue

& Capital Receipts) और अनुमानित व्यय (Expenditure) का एक वित्तीय विवरण है। यह सरकार की राजकोषीय नीति का मुख्य दस्तावेज होता है।

बजट के मुख्य घटक:

राजस्व बजट (Revenue Budget):

राजस्व प्राप्तियां (Revenue Receipts): वे प्राप्तियां जो न तो सरकार की देनदारी (Liability) बढ़ाती हैं और न ही परिसंपत्तियों (Assets) को कम करती हैं। इसमें कर राजस्व (आयकर, GST) और गैर-कर राजस्व (ब्याज, लाभांश, शुल्क) शामिल हैं।

राजस्व व्यय (Revenue Expenditure): सरकार के दैनिक कामकाज चलाने के लिए किया गया खर्च जिससे कोई संपत्ति नहीं बनती। उदाहरण: वेतन, पेंशन, सब्सिडी, ब्याज भुगतान।

पूंजीगत बजट (Capital Budget):

पूंजीगत प्राप्तियां (Capital Receipts): वे प्राप्तियां जो या तो देनदारी बढ़ाती हैं (ऋण लेना) या परिसंपत्तियों को कम करती हैं (विनिवेश - Disinvestment, ऋण वसूली)।

पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure): वह खर्च जिससे भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण होता है या देनदारियां कम होती हैं। उदाहरण: अस्पताल, सड़क निर्माण, ऋण का भुगतान।

30. घाटे के बजट के विभिन्न प्रकार: राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, और प्राथमिक घाटा में क्या अंतर है?

उत्तर:

बजट में जब सरकार का कुल खर्च उसकी कुल प्राप्तियों से अधिक होता है, तो इसे घाटे का बजट कहते हैं। लोक वित्त में तीन प्रमुख घाटे पढ़े जाते हैं:

राजस्व घाटा (Revenue Deficit):

सूत्र: $\text{राजस्व व्यय} - \text{राजस्व प्राप्तियां}$

अर्थ: यह दर्शाता है कि सरकार अपने नियमित और दैनिक कामकाज (वेतन, सब्सिडी आदि) को भी अपनी नियमित आय से पूरा नहीं कर पा रही है। यह स्थिति खराब मानी जाती है क्योंकि इसके लिए सरकार को उधार लेना पड़ता है।

राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit):

सूत्र: $\text{कुल व्यय} - (\text{राजस्व प्राप्तियां} + \text{गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां})$

अर्थ: यह सरकार की कुल उधारी (Total Borrowing) की आवश्यकता को दर्शाता है। यह दिखाता है कि सरकार को अपने कुल खर्चों को पूरा करने के लिए उस वर्ष कितना ऋण लेना पड़ेगा। यह देश की राजकोषीय सेहत का सबसे महत्वपूर्ण सूचक है।

प्राथमिक घाटा (Primary Deficit):

सूत्र: $\text{राजकोषीय घाटा} - \text{पुराने ऋणों पर ब्याज भुगतान (Interest Payments)}$

अर्थ: यह दर्शाता है कि चालू वर्ष के सरकारी कामकाज और नीतियों के कारण कितना घाटा हुआ है, यदि इसमें से अतीत में लिए गए ऋणों के ब्याज भार को हटा दिया जाए।

31. शून्य आधारित बजट (Zero-Based Budgeting - ZBB) क्या है? इसके लाभ और सीमाएं बताइए।

उत्तर:

शून्य आधारित बजट (Zero-Based Budgeting) बजट निर्माण की एक ऐसी विधि है जिसमें हर नए वित्तीय वर्ष के लिए बजट बनाते समय पिछले वर्ष के बजट या खर्च के आंकड़ों को आधार नहीं माना जाता। इसमें प्रत्येक विभाग को अपने हर एक कार्यक्रम और खर्च का औचित्य इस प्रकार सिद्ध करना पड़ता है जैसे कि वह कार्यक्रम शून्य (Zero) से शुरू हो रहा हो।

इसका प्रतिपादन पीटर प्यहर (Peter Phyr) ने 1970 के दशक में किया था।

ZBB के लाभ:

अनुत्पादक खर्चों की समाप्ति: जो पुरानी योजनाएं अब प्रासंगिक या प्रभावी नहीं रही हैं, उनकी समीक्षा कर उन्हें आसानी से बंद कर दिया जाता है।

संसाधनों का इष्टतम उपयोग: धन का आवंटन प्राथमिकताओं और प्रदर्शन के आधार पर होता है।

लागत में कमी: यह सरकारी विभागों में अपव्यय और फिजूलखर्ची पर रोक लगाता है।

सीमाएं:

अत्यधिक कागजी कार्रवाई: हर कार्यक्रम की नए सिरे से गहन समीक्षा करने में बहुत समय, श्रम और डेटा की आवश्यकता होती है।

मापन में कठिनाई: स्वास्थ्य, शिक्षा या रक्षा जैसे क्षेत्रों के दीर्घकालिक परिणामों को मौद्रिक रूप में मापना कठिन होता है।

कर्मचारियों का विरोध: पुरानी सुविधाओं और बजट में कटौती के डर से कर्मचारी इसका विरोध करते हैं।

32. निष्पादन बजट (Performance Budgeting) और परिणाम बजट (Outcome Budgeting) में क्या अंतर है?

उत्तर:

परंपरागत बजट केवल यह देखता था कि किस मद पर कितना पैसा खर्च (Input) स्वीकृत हुआ। इसके विपरीत, आधुनिक लोक वित्त में प्रदर्शन-आधारित तकनीकों का उपयोग किया जाता है:

निष्पादन बजट (Performance Budgeting):

अवधारणा: इसमें केवल खर्च की जाने वाली राशि को ही नहीं देखा जाता, बल्कि यह भी तय किया जाता है कि उस राशि से कितना भौतिक कार्य (Physical Output) पूरा होगा।

उदाहरण: यदि सड़क निर्माण के लिए ₹100 करोड़ दिए गए, तो निष्पादन बजट यह देखेगा कि कितनी किलोमीटर सड़क का निर्माण (Output) हुआ।

इसका ध्यान "पैसा कहाँ खर्च हुआ" से हटाकर "पैसा खर्च करके क्या प्राप्त हुआ" पर केंद्रित होता है।

परिणाम बजट (Outcome Budgeting):

अवधारणा: यह निष्पादन बजट से भी एक कदम आगे की प्रक्रिया है। यह केवल भौतिक आउटपुट को नहीं देखता, बल्कि समाज पर उसके वास्तविक प्रभाव या परिणाम (Qualitative Outcome) का आकलन करता है।

उदाहरण: यदि स्कूल बनाए गए (Output), तो परिणाम बजट यह मापेगा कि बच्चों की साक्षरता दर, नामांकन दर और शिक्षा की गुणवत्ता (Outcome) में कितना सुधार हुआ।

भारत में परिणाम बजट की शुरुआत 2005 में की गई थी ताकि बजटीय आवंटन का वास्तविक लाभ जनता तक पहुँचना सुनिश्चित किया जा सके।

33. वित्तीय संघवाद (Fiscal Federalism) क्या है? इसके मुख्य सिद्धांत बताइए।

उत्तर:

वित्तीय संघवाद (Fiscal Federalism) लोक वित्त का वह क्षेत्र है जो एक बहुस्तरीय सरकारी ढांचे (जैसे केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारें) के बीच वित्तीय शक्तियों, कर लगाने के अधिकारों, और सार्वजनिक व्यय की जिम्मेदारियों के बंटवारे का अध्ययन करता है।

वित्तीय संघवाद के मुख्य सिद्धांत:

वित्तीय समरूपता का सिद्धांत (Principle of Fiscal Equivalence): जो सरकार किसी सार्वजनिक सेवा का लाभ जिस क्षेत्र तक पहुँचाती है, उस सेवा का खर्च और कर लगाने का अधिकार उसी स्तर की सरकार को होना चाहिए।

केंद्रीयकरण बनाम विकेंद्रीकरण (Oates' Decentralization Theorem):

राष्ट्रीय रक्षा, मुद्रा, और स्थिरीकरण जैसे कार्य केंद्रीय सरकार के पास होने चाहिए।

स्थानीय आवश्यकता वाली वस्तुएं (जैसे स्ट्रीट लाइट, जल निकासी) स्थानीय सरकारों के पास होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें स्थानीय प्राथमिकताओं की बेहतर जानकारी होती है।

कुशलता का सिद्धांत: कर लगाने की शक्ति उस स्तर को दी जानी चाहिए जो उसे सबसे कुशलतापूर्वक एकत्र कर सके (जैसे एकीकृत बाजार के लिए GST केंद्र/राज्य समन्वय द्वारा)।

राजकोषीय विषमता दूर करना: राज्यों के बीच आर्थिक विषमताओं को कम करने के लिए केंद्र से राज्यों को वित्तीय हस्तांतरण (Grants) होना चाहिए।

34. लंबवत असंतुलन (Vertical Fiscal Imbalance) और क्षैतिज असंतुलन (Horizontal Fiscal Imbalance) क्या हैं?

उत्तर:

संघीय व्यवस्थाओं में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों और उत्तरदायित्वों में असंतुलन पाया जाता है, जिसे दो भागों में बांटा जाता है:

लंबवत राजकोषीय असंतुलन (Vertical Fiscal Imbalance - VFI):

अर्थ: यह असंतुलन सरकार के विभिन्न स्तरों (अर्थात् केंद्र सरकार और राज्य सरकारों) के बीच होता है।

कारण: आमतौर पर संविधान द्वारा अधिक राजस्व देने वाले और लोचदार कर (जैसे आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क) केंद्र सरकार को सौंप दिए जाते हैं। इसके विपरीत, अधिक व्यय वाली सामाजिक जिम्मेदारियाँ (शिक्षा,

स्वास्थ्य, पुलिस, कृषि) राज्यों को दी जाती हैं।

परिणाम: केंद्र के पास अपनी जरूरतों से अधिक आय होती है, जबकि राज्यों के पास अपने खर्चों की तुलना में आय कम होती है। इसे अनुदान और कर-साझाकरण (Tax Sharing) द्वारा ठीक किया जाता है।

क्षैतिज राजकोषीय असंतुलन (Horizontal Fiscal Imbalance - HFI):

अर्थ: यह असंतुलन एक ही स्तर की विभिन्न राज्य सरकारों के बीच होता है (जैसे महाराष्ट्र बनाम बिहार)।

कारण: राज्यों के बीच प्राकृतिक संसाधनों, औद्योगीकरण, कर आधार, और आर्थिक विकास के स्तर में अंतर होता है।

परिणाम: अमीर राज्य आसानी से अधिक राजस्व एकत्र कर लेते हैं, जबकि पिछड़े राज्य अपने नागरिकों को न्यूनतम सार्वजनिक सेवाएं देने में भी असमर्थ होते हैं। इसे संतुलित करने के लिए विशेष वित्त आयोग हस्तांतरण सूत्र अपनाता है।

35. भारत में वित्त आयोग (Finance Commission) की भूमिका और कार्य क्या हैं?

उत्तर:

भारत में वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जिसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत हर पांच साल में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यह भारत में वित्तीय संघवाद को संतुलित रखने वाली सबसे प्रमुख संस्था है।

वित्त आयोग के मुख्य कार्य:

कर राजस्व का बंटवारा (Vertical Devolution): केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए गए विभाज्य कर पूल (Divisible Pool of Taxes) में से राज्यों को कितना हिस्सा दिया जाए, इसकी सिफारिश करना (उदा. 15वें वित्त आयोग ने 41% की सिफारिश की)।

राज्यों के बीच करों का आवंटन (Horizontal Devolution): राज्यों को मिलने वाले कुल हिस्से को विभिन्न राज्यों के बीच किस सूत्र (जैसे जनसंख्या, आय में अंतर, वन क्षेत्र, राजकोषीय अनुशासन) के आधार पर बांटा जाए।

सहायता अनुदान (Grants-in-Aid): संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत भारत की संचित निधि में से राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान के सिद्धांतों को तय करना (उदा. राजस्व घाटा अनुदान, आपदा प्रबंधन अनुदान)।

स्थानीय निकायों के संसाधन बढ़ाना: राज्यों के वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के उपाय सुझाना।

वित्त आयोग की सिफारिशें भारत में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने और राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता की रक्षा करने में निर्णायक होती हैं।

36. वस्तु एवं सेवा कर (GST) क्या है? इसके फायदे और चुनौतियाँ बताइए।

उत्तर:

वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax - GST) भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया एक व्यापक, बहु-स्तरीय, गंतव्य-आधारित (Destination-based) अप्रत्यक्ष कर है। इसने केंद्र और राज्यों के दर्जनों पुराने अप्रत्यक्ष करों (जैसे उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट, मनोरंजन कर) को समाप्त करके "एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार" की अवधारणा को साकार किया।

GST के प्रमुख फायदे:

करों के ऊपर कर (Cascading Effect)की समाप्ति: इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC)प्रणाली के कारण कर केवल मूल्य संवर्धन (Value Addition) पर ही लगता है, जिससे कर पर कर लगाना बंद हो गया।

एकीकृत भारतीय बाजार: राज्यों की सीमाओं पर लगने वाले चेकपोस्ट खत्म हुए, जिससे माल की आवाजाही आसान और सस्ती हुई।

कर अनुपालन में वृद्धि: पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन (GSTN portal)होने से कर चोरी में कमी आई है और कर आधार बढ़ा है।

चुनौतियाँ:

जटिल दर संरचना: कई स्लैब (5%, 12%, 18%, 28%) होने से वर्गीकरण के विवाद उत्पन्न होते हैं।

तकनीकी समस्याएं: छोटे व्यापारियों के लिए आईटी प्रणाली और अनुपालन (Filing returns) की लागत में वृद्धि।

राज्यों की स्वायत्तता का मुद्दा: राज्यों ने अपने स्वतंत्र कर लगाने के अधिकार खो दिए हैं, जिससे वे राजस्व के लिए केंद्र पर अधिक निर्भर हो गए हैं।

37. FRBM अधिनियम, 2003 (Fiscal Responsibility and Budget Management Act) क्या है?

उत्तर:

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (FRBM Act), 2003 भारत सरकार द्वारा राजकोषीय अनुशासन लाने, अंतर-पीढ़ीगत समता सुनिश्चित करने और दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता बनाए रखने के लिए पारित किया गया एक कानून है।

FRBM अधिनियम के मुख्य उद्देश्य:

राजकोषीय घाटे में कमी: सरकार के राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे को क्रमिक रूप से कम करना। (मूल लक्ष्य राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3% तक लाना और राजस्व घाटे को पूरी तरह समाप्त करना था)।

आरबीआई से उधारी पर रोक: सरकार द्वारा अपने घाटे को पूरा करने के लिए सीधे भारतीय रिजर्व बैंक से प्राथमिक बाजार में नोट छपवाकर (Monetized Deficit) कर्ज लेने पर प्रतिबंध लगाना।

पारदर्शिता बढ़ाना: सरकार के लिए संसद में अपने बजट के साथ तीन प्रमुख नीतिगत दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया:

मध्यम अवधि राजकोषीय नीति कथन (Medium-Term Fiscal Policy Statement)

राजकोषीय नीति रणनीति कथन (Fiscal Policy Strategy Statement)

मैक्रो-इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एसेसमेंट (Macro-Economic Framework Assessment)

लचीलापन (Escape Clause): राष्ट्रीय सुरक्षा, प्राकृतिक आपदा, या गंभीर आर्थिक मंदी के समय सरकार को राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों से भटकने की अनुमति (Escape Clause) एन. के. सिंह समिति की सिफारिशों के तहत दी गई है।

38. घाटे का वित्तपोषण (Deficit Financing) क्या है? इसके आर्थिक प्रभाव बताइए।

उत्तर:

जब सरकार का कुल व्यय उसकी कुल प्राप्तियों से अधिक होता है, तो इस घाटे को पूरा करने के लिए अपनाई गई वित्तीय प्रक्रियाओं को घाटे का वित्तपोषण (Deficit Financing) कहा जाता है। भारत जैसे विकासशील देशों में बुनियादी ढाँचे और विकास योजनाओं के वित्तपोषण के लिए इसका व्यापक उपयोग किया जाता है।

घाटे के वित्तपोषण के मुख्य तरीके:

केंद्रीय बैंक (RBI) से सरकार द्वारा अपनी सरकारी प्रतिभूतियों (Government Securities) के बदले ऋण लेना (जिसके लिए नए नोट छापे जाते हैं)।

सरकार द्वारा अपने पास जमा नकदी शेष (Cash Balances) का उपयोग करना।

बाजार से उधार लेना।

आर्थिक प्रभाव:

सकारात्मक प्रभाव: यदि इस धन का उपयोग उत्पादक क्षेत्रों (जैसे सड़कें, सिंचाई, उद्योग) में परिसंपत्ति निर्माण के लिए किया जाता है, तो इससे उत्पादन बढ़ता है, रोजगार पैदा होता है और आर्थिक वृद्धि दर तेज होती है (केन्स का दृष्टिकोण)।

नकारात्मक प्रभाव (मुद्रास्फीति का खतरा): यदि नए नोट छापकर घाटा पूरा किया जाता है और अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन तुरंत नहीं बढ़ता, तो बाजार में अतिरिक्त धन आपूर्ति (Money Supply) आ जाती है। इससे "अधिक धन, कम वस्तुओं का पीछा करता है" और तीव्र मुद्रास्फीति (Inflation) पैदा हो जाती है, जो गरीबों को सबसे अधिक प्रभावित करती है।

39. भीड़ प्रभाव (Crowding-out Effect) और क्राउडिंग-इन प्रभाव (Crowding-in Effect) क्या हैं?

उत्तर:

राजकोषीय नीति में सरकारी खर्च और निजी निवेश के बीच संबंध को समझने के लिए ये दो विपरीत अवधारणाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं:

भीड़ प्रभाव (Crowding-out Effect):

अवधारणा: जब सरकार अपने घाटे को पूरा करने के लिए वित्तीय बाजार से बहुत भारी मात्रा में ऋण लेती है, तो बाजार में निजी क्षेत्र के लिए ऋण योग्य कोष (Loanable Funds) की कमी हो जाती है।

प्रक्रिया: अत्यधिक सरकारी उधारी से बाजार में ब्याज दरें (Interest Rates) बढ़ जाती हैं। उच्च ब्याज दरों के कारण निजी कंपनियों के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाता है, जिससे वे अपने नए प्रोजेक्ट्स और निवेश को रद्द या कम कर देती हैं।

निष्कर्ष: सरकारी व्यय में वृद्धि ने निजी निवेश को बाजार से "बाहर" धकेल दिया।

क्राउडिंग-इन प्रभाव (Crowding-in Effect):

अवधारणा: यह परिस्थिति तब बनती है जब सरकारी खर्च वास्तव में निजी निवेश को बढ़ावा देता है और उसे आकर्षित करता है।

प्रक्रिया: यदि सरकार अपना पैसा बुनियादी ढाँचे (सड़कें, बंदरगाह, रेलवे, बिजली) पर खर्च करती है, तो इससे निजी क्षेत्र की उत्पादन लागत कम हो जाती है और व्यापार करने की सुगमता बढ़ती है। इससे उत्साहित होकर निजी

कंपनियां अधिक निवेश करती हैं।

निष्कर्ष: सरकारी पूंजीगत व्यय निजी निवेश को "अंदर" खींचता है।

40. लिंडाहल का कर मॉडल (Lindahl's Model of Voluntary Exchange) क्या है?

उत्तर:

स्वीडिश अर्थशास्त्री एरिक लिंडाहल (Erik Lindahl) ने 1919 में सार्वजनिक वस्तुओं के मूल्य निर्धारण और प्रावधान के लिए 'ऐच्छिक विनिमय मॉडल' (Voluntary Exchange Model) प्रस्तुत किया। यह मॉडल दिखाता है कि सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन और उनके लिए करों का बंटवारा बाजार में निजी वस्तुओं की तरह कैसे तय किया जा सकता है।

मॉडल की मुख्य विशेषताएं:

लिंडाहल ने माना कि दो उपभोक्ता (या समूह) हैं और वे सामूहिक रूप से यह तय करते हैं कि उन्हें कितनी मात्रा में सार्वजनिक वस्तु चाहिए और प्रत्येक इसके लिए कर का कितना प्रतिशत (Tax Price) चुकाएगा।

संतुलन (Lindahl Equilibrium): संतुलन तब प्राप्त होता है जब दोनों उपभोक्ता सार्वजनिक वस्तु की एक ही मात्रा पर सहमत हो जाते हैं, और उनके द्वारा चुकाई जाने वाली कर दरों का योग वस्तु की कुल सीमांत लागत (100%) के बराबर होता है।

इसे 'छद्म-बाजार संतुलन' (Pseudo-market Equilibrium) भी कहा जाता है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपनी सीमांत उपयोगिता के अनुसार अपनी स्वेच्छा से कर चुकाता है।

सीमाएं:

लिंडाहल मॉडल यह मानकर चलता है कि लोग अपनी प्राथमिकताओं को ईमानदारी से प्रकट करेंगे। लेकिन व्यावहारिक रूप से, लोग 'फ्री-राइडर' बनने के लिए अपनी वास्तविक उपयोगिता को छुपाते हैं, जिससे यह मॉडल केवल सैद्धांतिक रह जाता है।

41. पीगू का कल्याणकारी अर्थशास्त्र और पीगोवियन कर (Pigouvian Tax) क्या है?

उत्तर:

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ए. सी. पीगू (A.C. Pigou) ने कल्याणकारी अर्थशास्त्र और लोक वित्त में ऋणात्मक बाह्यताओं (Negative Externalities) को नियंत्रित करने के लिए कर के उपयोग का सिद्धांत प्रस्तुत किया।

पीगोवियन कर (Pigouvian Tax) की अवधारणा:

जब कोई कारखाना या उत्पादक प्रदूषण फैलाता है या समाज को नुकसान पहुँचाता है, तो वह केवल अपनी 'निजी लागत' (Private Cost) को देखता है और 'सामाजिक लागत' (Social Cost) को नजरअंदाज करता है। इसके परिणामस्वरूप उस हानिकारक वस्तु का अत्यधिक उत्पादन होता है।

पीगू का तर्क था कि सरकार को उस गतिविधि पर प्रदूषण या क्षति की मात्रा के बराबर कर (Tax) लगा देना चाहिए।

इस कर को लगाने से उत्पादक को अपनी ऋणात्मक बाह्यता का आंतरीकरण (Internalize the Externality) करने पर मजबूर होना पड़ता है।

परिणाम: कर लगने से उत्पादक की लागत बढ़ जाती है, जिससे वह उत्पादन घटाकर उसे सामाजिक रूप से इष्टतम स्तर (Socially Optimum Level) पर ले आता है।

उदाहरण: कार्बन टैक्स (Carbon Tax), पर्यावरण प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों या कारखानों पर कर, और सिगरेट पर 'सिन टैक्स'। यह कर बाजार विफलता को सुधारने और सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने का एक माध्यम है।

42. कोसे प्रमेय (Coase Theorem) क्या है और यह सार्वजनिक वित्त से कैसे संबंधित है?

उत्तर:

नोबेल पुरस्कार विजेता रोनल्ड कोसे (Ronald Coase) द्वारा 1960 में प्रतिपादित 'कोसे प्रमेय' वाह्यताओं (Externalities) और बाजार विफलता के समाधान के लिए सरकारी हस्तक्षेप के विकल्प के रूप में एक मौलिक विचार प्रस्तुत करता है।

कोसे प्रमेय का कथन:

यदि संपत्ति के अधिकार (Property Rights) स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं और सौदेबाजी की लागत (Transaction Costs) शून्य या बहुत कम है, तो निजी पक्ष (Private Parties) सरकारी हस्तक्षेप या करों के बिना भी, आपसी बातचीत और सौदेबाजी (Bargaining) के माध्यम से वाह्यताओं की समस्या का कुशल समाधान निकाल सकते हैं।

उदाहरण:

यदि किसी डॉक्टर के क्लिनिक के बगल में एक बेकर की मशीन भारी शोर करती है:

यदि डॉक्टर के पास शांत माहौल का अधिकार है, तो बेकर डॉक्टर को शोर सहने के लिए मुआवजा दे सकता है या नई शांत मशीन लगा सकता है।

यदि बेकर के पास शोर करने का अधिकार है, तो डॉक्टर बेकर को मशीन बंद करने या समय बदलने के लिए पैसे दे सकता है।

परिणाम दोनों ही स्थितियों में कुशल (Efficient) होगा।

लोक वित्त में प्रासंगिकता:

यह प्रमेय दर्शाता है कि सरकार को हर वाह्यता पर पीगोवियन कर लगाने की आवश्यकता नहीं है; कई मामलों में केवल संपत्ति के अधिकार तय करके और लेनदेन लागत कम करके बाजार को स्वयं समस्या हल करने दी जा सकती है।

43. कर की लोचशीलता (Tax Elasticity) और कर की उछाल (Tax Buoyancy) में क्या अंतर है?

उत्तर:

कर प्रणाली की उत्पादकता और प्रतिक्रियाशीलता को मापने के लिए लोक वित्त में 'टैक्स इलास्टिसिटी' और 'टैक्स बायेंसी' दो प्रमुख सूचक हैं:

कर की लोचशीलता (Tax Elasticity):

अर्थ: यह दर्शाता है कि कर की दरों या कर नियमों में बिना कोई बदलाव किए, केवल राष्ट्रीय आय (GDP) में वृद्धि होने के कारण स्वचालित रूप से कर राजस्व में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आता है।

सूत्र:
$$\frac{\text{कर राजस्व में \% परिवर्तन (बिना विवेकाधीन बदलाव के)}}{\text{जीडीपी में \% परिवर्तन}}$$

\$

यह कर आधार की अंतर्निहित वृद्धि क्षमता को मापता है।

कर की उछाल (Tax Buoyancy):

अर्थ: यह राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ-साथ कर की दरों में बदलाव, नए कर लगाने और कर कवरेज बढ़ाने जैसे सरकारी नीतिगत उपायों (Discretionary Changes) के कुल प्रभाव के कारण कर राजस्व में होने वाली कुल वृद्धि को मापता है।

सूत्र:
$$\frac{\text{कुल कर राजस्व में \% परिवर्तन (सभी बदलावों सहित)}}{\text{जीडीपी में \% परिवर्तन}}$$

निष्कर्ष: यदि कर की उछाल 1 से अधिक (>1) है, तो इसका अर्थ है कि जीडीपी की तुलना में कर संग्रह तेजी से बढ़ रहा है। एक स्वस्थ कर प्रणाली में लोचशीलता और उछाल दोनों उच्च होने चाहिए।

44. कर टालमटोल (Tax Avoidance) और कर चोरी (Tax Evasion) में क्या अंतर है?

उत्तर:

करदाता अपने कर दायित्व को कम करने के लिए दो अलग-अलग तरीकों का उपयोग करते हैं, जिनके कानूनी और नैतिक परिणाम पूरी तरह भिन्न होते हैं:

कर टालमटोल (Tax Avoidance):

प्रकृति: यह कानूनी (Legal) तरीका है।

व्याख्या: इसमें करदाता कर कानूनों में मौजूद कमियों (Loop holes), छूटों (Deductions) और प्रावधानों का चतुरता से उपयोग करके अपने कर को कम करता है।

उदाहरण: सरकार द्वारा स्वीकृत बचत योजनाओं (जैसे PPF, जीवन बीमा) में निवेश करके कर योग्य आय को घटाना।

हालांकि यह कानून के दायरे में है, लेकिन यह कानून की भावना (Spirit of Law) के विपरीत माना जाता है।

कर चोरी (Tax Evasion):

प्रकृति: यह गैर-कानूनी (Illegal) और एक अपराध है।

व्याख्या: इसमें करदाता जानबूझकर गलत जानकारी देकर, आय को छुपाकर, फर्जी खर्च दिखाकर या बिक्री का हिसाब न रखकर धोखे से कर देने से बचता है।

उदाहरण: बिना बिल के नकद में व्यापार करना और काले धन का सृजन करना।

इसके पाए जाने पर भारी जुर्माना, संपत्ति जब्त होना और जेल की सजा हो सकती है।

45. समानीकरण अनुदान (Equalization Grants) क्या हैं? इनका संघीय वित्त में क्या महत्व है?

उत्तर:

समानीकरण अनुदान (Equalization Grants) वित्तीय संघवाद में केंद्रीय सरकार द्वारा विभिन्न प्रांतीय या राज्य सरकारों को दिए जाने वाले वे हस्तांतरण हैं, जिनका उद्देश्य राज्यों के बीच मौजूद राजस्व क्षमताओं के अंतर को समाप्त करना होता है।

इनकी आवश्यकता क्यों होती है?

एक ही देश के भीतर कुछ राज्य (जैसे औद्योगिक राज्य) अपने मजबूत कर आधार के कारण बहुत अधिक राजस्व एकत्र कर लेते हैं, जबकि कुछ पिछड़े या पहाड़ी राज्य अपने नागरिकों से पर्याप्त कर एकत्र करने में असमर्थ होते हैं।

समानीकरण अनुदान का उद्देश्य:

समान सार्वजनिक सेवा स्तर: इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि देश का कोई भी नागरिक चाहे वह किसी भी राज्य में रहता हो, उसे कर की एक समान दर पर प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, और सड़कों जैसी न्यूनतम मानक सार्वजनिक सेवाएं (Minimum Standard Public Services) प्राप्त हों।

क्षेत्रीय असमानता कम करना: यह अमीर राज्यों से एकत्र करें के एक हिस्से को पिछड़े राज्यों की ओर हस्तांतरित करता है।

कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारत (वित्त आयोग के 'आय अंतर/Income Distance' मानदंड के माध्यम से) जैसी संघीय प्रणालियों में समानीकरण अनुदान राष्ट्रीय एकता और सामाजिक न्याय का एक प्रमुख साधन हैं।

46. सार्वजनिक ऋण का अंतर-पीढ़ीगत भार (Intergenerational Equity and Burden of Public Debt) क्या है?

उत्तर:

सार्वजनिक ऋण का एक सबसे चर्चित और बहस योग्य विषय यह है कि "क्या आज की सरकार द्वारा लिया गया कर्ज आने वाली पीढ़ी (Future Generation) पर भार डालता है?" इसे ही अंतर-पीढ़ीगत भार का प्रश्न कहते हैं।

विभिन्न अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण:

परंपरागत दृष्टिकोण (Classical View & Lerner's View):

आंतरिक ऋण: यदि ऋण आंतरिक है, तो यह आने वाली पीढ़ी पर कुल मिलाकर कोई वास्तविक भार नहीं डालता, क्योंकि भविष्य में जब टैक्स देकर कर्ज चुकाया जाएगा, तो टैक्स देने वाले भी उसी पीढ़ी के होंगे और ब्याज प्राप्त करने वाले (बॉन्ड धारक) भी उसी पीढ़ी के होंगे। धन केवल एक भारतीय की जेब से दूसरे भारतीय की जेब में जाएगा।

बाह्य ऋण: बाह्य ऋण भविष्य की पीढ़ी पर वास्तविक भार डालता है, क्योंकि भविष्य में देश के वास्तविक संसाधन (विदेशी मुद्रा) बाहर भेजने पड़ेंगे।

आधुनिक दृष्टिकोण (Buchanan & Modigliani View):

यदि आज लिया गया ऋण उपभोग (Consumption) पर खर्च कर दिया जाता है, तो आने वाली पीढ़ी को केवल कर चुकाने का बोझ मिलता है बिना किसी नई संपत्ति के।

लेकिन यदि ऋण का उपयोग सड़कों, बांध, और विश्वविद्यालय (Capital Assets) बनाने में होता है, तो आने वाली पीढ़ी को अधिक समृद्ध अर्थव्यवस्था मिलती है, जो ऋण के भार से कहीं अधिक लाभदायक होती है।

47. मुंडेल-फ्लेमिंग मॉडल में राजकोषीय नीति की प्रभावशीलता (Fiscal Policy in Mundell-Fleming Model) क्या है?

उत्तर:

मुंडेल-फ्लेमिंग मॉडल (Mundell-Fleming Model) एक खुली अर्थव्यवस्था (Open Economy) का अध्ययन करता है जहाँ पूंजी की पूर्ण गतिशीलता (Perfect Capital Mobility) होती है। इसमें राजकोषीय नीति की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि देश में विनिमय दर प्रणाली (Exchange Rate Regime) कैसी है:

स्थिर विनिमय दर प्रणाली (Fixed Exchange Rate System):

परिणाम: राजकोषीय नीति अत्यधिक प्रभावी (Extremely Effective) होती है।

प्रक्रिया: जब सरकार व्यय बढ़ाती है (Expansionary Fiscal Policy), तो आईएस वक्र दाईं ओर खिसकता है, जिससे देश में ब्याज दरें बढ़ती हैं। उच्च ब्याज दरों के कारण विदेशी पूंजी तेजी से देश में आती है। विनिमय दर को स्थिर रखने के लिए केंद्रीय बैंक को बाजार से विदेशी मुद्रा खरीदनी पड़ती है और घरेलू मुद्रा की आपूर्ति (Money Supply) बढ़ानी पड़ती है। इससे उत्पादन और रोजगार में भारी वृद्धि होती है।

लचीली/परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली (Floating Exchange Rate System):

परिणाम: राजकोषीय नीति पूरी तरह अप्रभावी (Completely Ineffective) हो जाती है।

प्रक्रिया: सरकारी व्यय बढ़ने से ब्याज दर बढ़ती है और विदेशी पूंजी आती है। इससे घरेलू मुद्रा का मूल्य बढ़ता है (Currency Appreciation)। मुद्रा मजबूत होने से निर्यात महंगे और आयात सस्ते हो जाते हैं, जिससे शुद्ध निर्यात (Net Exports) गिर जाता है। यह गिरावट सरकारी व्यय के प्रभाव को शून्य कर देती है।

48. क्राउडिंग-आउट और IS-LM वक्र ढांचे में राजकोषीय नीति का प्रभाव स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

हिंक्स-हैनसन का IS-LM मॉडल वस्तु बाजार (Goods Market) और मुद्रा बाजार (Money Market) में एक साथ संतुलन को दर्शाता है। इस ढांचे में विस्तारवादी राजकोषीय नीति (सरकारी व्यय में वृद्धि या कर में कमी) के प्रभाव को समझा जा सकता है:

प्रक्रिया और क्राउडिंग-आउट:

जब सरकार अपने व्यय (ΔG) में वृद्धि करती है, तो वस्तु बाजार में मांग बढ़ती है और IS वक्र दाईं ओर (Rightward) खिसक जाता है।

IS वक्र के खिसकने से राष्ट्रीय आय (Y) बढ़ती है।

राष्ट्रीय आय बढ़ने पर लोग लेन-देन के लिए मुद्रा की अधिक मांग करते हैं। मुद्रा की पूर्ति (LM वक्र) स्थिर होने के कारण मुद्रा बाजार में ब्याज दर (r) बढ़ जाती है।

इस बढ़ी हुई ब्याज दर के कारण निजी निवेशक हतोत्साहित होते हैं और निजी निवेश (I) घट जाता है।

IS-LM में क्राउडिंग-आउट की मात्रा:

पूर्ण क्राउडिंग-आउट (Full Crowding-out): यदि LM वक्र पूरी तरह लंबवत (Vertical - क्लासिकल स्थिति) है, तो सरकारी व्यय से केवल ब्याज दर बढ़ेगी, आय में कोई वृद्धि नहीं होगी।

शून्य क्राउडिंग-आउट (No Crowding-out): यदि LM वक्र पूरी तरह क्षैतिज (Horizontal - केन्स का तरलता जाल / Liquidity Trap) है, तो ब्याज दर नहीं बढ़ेगी और राजकोषीय नीति अपने पूर्ण गुणक प्रभाव (Full Multiplier Effect) के साथ काम करेगी।

49. छाया मूल्य निर्धारण (Shadow Pricing) और लागत-लाभ विश्लेषण (Cost-Benefit

Analysis) क्या है?

उत्तर:

सार्वजनिक क्षेत्र की योजनाओं और परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए 'लागत-लाभ विश्लेषण' (CBA) एक प्रमुख उपकरण है। निजी क्षेत्र केवल वित्तीय लाभ-हानि देखता है, जबकि सरकार को सामाजिक दृष्टि से निर्णय लेना होता है।

1. लागत-लाभ विश्लेषण (Cost-Benefit Analysis):

इसमें किसी सार्वजनिक परियोजना (जैसे बांध या हाईवे) की कुल सामाजिक लागतों (Social Costs) और कुल सामाजिक लाभों (Social Benefits) की तुलना की जाती है। यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present Value - NPV) धनात्मक है, तो परियोजना को स्वीकृत किया जाता है।

2. छाया मूल्य (Shadow Pricing) की भूमिका:

बाजार मूल्य प्रणाली में अक्सर एकाधिकार, करों, सब्सिडी, और बाधाओं के कारण बाजार मूल्य किसी वस्तु या संसाधन की वास्तविक सामाजिक अवसर लागत (True Social Opportunity Cost) को नहीं दर्शाते। ऐसी स्थिति में अर्थशास्त्री छाया मूल्य (Shadow Price) का प्रयोग करते हैं।

उदाहरण 1 (बेरोजगारी): यदि किसी पिछड़े क्षेत्र में भारी बेरोजगारी है और सरकार परियोजना के लिए मजदूरों को काम पर रखती है, तो उनका बाजार वेतन ₹400/दिन हो सकता है, लेकिन उनका छाया मूल्य (अवसर लागत) लगभग शून्य हो सकता है, क्योंकि वे अन्यथा बेकार बैठे रहते।

उदाहरण 2 (प्रदूषण): कारखाने से फैलने वाले प्रदूषण का बाजार मूल्य शून्य होता है, लेकिन CBA में इसके स्वास्थ्य नुकसान का एक 'छाया मूल्य' जोड़ना आवश्यक होता है।

50. जेंडर बजटिंग (Gender Budgeting) क्या है? इसका सामाजिक-आर्थिक महत्व क्या है?

उत्तर:

जेंडर बजटिंग (Gender Budgeting) महिलाओं के लिए एक अलग बजट बनाना नहीं है, बल्कि यह सामान्य बजट का ही एक लैंगिक परिप्रेक्ष्य (Gender Lens) से विश्लेषण और पुनर्गठन करने की एक राजकोषीय प्रक्रिया है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार की कराधान और व्यय नीतियां पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से लाभ पहुंचाएँ और समाज में लैंगिक असमानता को दूर करें।

भारत में जेंडर बजटिंग की औपचारिक शुरुआत 2005-06 के बजट में की गई थी।

जेंडर बजटिंग के दो मुख्य भाग:

भाग A (Part A): ऐसी योजनाएं जो 100% महिलाओं के लिए लक्षित हैं (जैसे मातृत्व लाभ योजनाएं, महिला हॉस्टल, उज्ज्वला योजना)।

भाग B (Part B): ऐसी योजनाएं जिनमें कम से कम 30% से 99% तक लाभ महिलाओं को दिए जाते हैं (जैसे मनरेगा, आवास योजना, कौशल विकास)।

सामाजिक-आर्थिक महत्व:

महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण होता है और श्रम बल सहभागिता (FLFP) बढ़ती है।

यह संसाधनों के आवंटन में मौजूद अनदेखी लैंगिक विषमताओं को उजागर करता है।

मानव विकास सूचकांक (HDI) में सुधार लाता है, जिससे देश की कुल जीडीपी और सामाजिक कल्याण में टिकाऊ वृद्धि होती है।